

नहरों, नलकूपों, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली आदि के संचालन में वैकल्पिक ऊर्जा उपयोगी एवं सौर जनित हरित ऊर्जा से सिंचाई प्रणालियों के संचालन से विद्युत की खपत कम तथा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा-डा0 महेन्द्र सिंह।

लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2019

उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा है कि वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई विभाग की विभिन्न सिंचाई प्रणालियों जैसे नलकूप, नहरें, लिफ्ट इरीगेशन, जलाशयों, बंधों आदि को कैसे संचालित किया जा सकता है, इसको लेकर देश विदेश की लगभग 33 कंपनियां दो दिन तक अपना प्रस्तुतीकरण देकर प्रदेश के सिंचाई विभाग के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इनके सहयोग से 30प्र0 को सौर ऊर्जा के मामले में देश का नम्बर-1 प्रदेश बनाने में मदद मिलेगी।

जलशक्ति मंत्री आज यहां डा0 राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन तेलीबाग के सभागार में सौरजनित हरित ऊर्जा का सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर प्रणालियों, राजकीय नलकूपों, खाली जमीनों का उपयोग कर निजी क्षेत्र के सहयोग से सौर ऊर्जा उत्पादन, परिचालन व उपयोग में भागीदारी के माध्यम से उपयोगी जल सिंचाई प्रबन्धन विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी के शुभारम्भ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

डा0 महेन्द्र सिंह ने 30प्र0 के प्राकृतिक संसाधनों को रेखांकित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बड़े भू-भाग वाला प्रदेश होने के साथ ही यहां लम्बे समय तक सूरज का प्रकाश बना रहता है, जिसका उपयोग करके सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यहां पर लाखों किलोमीटर लम्बाई में नहरें तथा अन्य सिंचाई प्रणालियां हैं। इसके अलावा बड़े जलाशय, विशाल भूमि बैंक, बड़े बांध, जलाशय, नहरें आदि में सौर ऊर्जा का प्रयोग कर, इन्हें चलाया और सौर ऊर्जा बनायी जा सकती है।

जलशक्ति मंत्री ने तेजी से पर्यावरण क्षरण तथा क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस के दुष्परिणाम से ओजोन परतों के नुकसान पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देकर कम से कम बिजली का उपयोग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जलशक्ति विभाग के अधीन सिंचाई विभाग की विभिन्न प्रणालियों में सोलर एनर्जी का उपयोग करके नलकूप व नहरों का संचालन करके बिजली बचायी जा सकती है। साथ ही इसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सकता है। उन्होंने सिंचाई विभाग की बेकार खाली जमीनों तथा नहरों के किनारे, पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास, जलाशयों व बंधों पर सोलर पैनल स्थापित कर सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ड्रिप व स्प्रींकलर इरीगेशन में इसका उपयोग करके कम पानी खपत से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

इस मौके पर जलशक्ति राज्यमंत्री श्री बलदेव सिंह औलख ने सौर ऊर्जा के माध्यम से क्रांति लाने का सुझाव देते हुए कहा कि इसको अपनाने से प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की जमीनों से अवैध कब्जे को हटाकर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाय।

मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री के०वी० राजू तथा विशेष सचिव सिंचाई डा० सारिका मोहन ने इस संगोष्ठी की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री के०वी० राजू ने कहा कि विदेशों तथा देश के कोने-कोने से आये सौर ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि जलसंसाधन प्रबंधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में प्रस्तुतीकरण कर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे।

इस अवसर पर सौर ऊर्जा व जल प्रबंधन से संबंधित 19 कंपनियों ने अपना प्रस्तुतीकरण करके अपने संसाधन, अनुभव, दक्षता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इन कंपनियों में इटली की एक, कोरिया की 02, तथा 18 कंपनियां भारत के कोने-कोने से आयी हुई हैं। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपनी विशेषताओं, सौर ऊर्जा उत्पादन तथा जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों को साझा किया।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जलसंसाधन श्री टी० वेंकटेश, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता यांत्रिक श्री देवेन्द्र अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता यांत्रिक श्री नवीन कपूर, प्रमुख अभियन्ता पैक्ट श्री ए०के० सेंगर सहित सौर जनित हरित ऊर्जा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।